

26

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क० 575-दो/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-11
पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 314/2010-11 अपील.

- 1- श्रीमती गंगादेवी विधवा पत्नी स्व. शंकरदीन सेन
- 2- मुकुटबिहारी सेन तनय स्व. शंकरदीन सेन
- 3- मुकेश कुमार सेन स्व. शंकरदीन सेन
- 4- सूरजकुमार सेन स्व. शंकरदीन सेन, अव्यस्क संरक्षक माँ गंगादेवी
- 5- श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी शोभनाथ सेन पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
सभी निवासी मोहल्ला पाण्डेनटोला, सिटी कोतवाली, तह. हुजूर
- 6- श्रीमती सन्तोष देवी धर्मपत्नी रामभजन सेन पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि० ग्राम बेढौआ, थाना बेकुण्ठपुर, तह. सिरमौर
- 7- श्रीमती विद्यादेवी धर्मपत्नी दिनेशकमार पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि० ग्राम नौढ़िया, तहसील एवं जिला सीधी
- 8- श्रीमती सरस्वती देवी धर्मपत्नी रमेशकुमार पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि० ग्राम नौढ़िया, तहसील एवं जिला सीधी
- 9- श्रीमती लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी अजयकुमार पुत्री स्व. शंकरदीन
नि० ग्राम पटौता, तहसील गुढ़, जिला रीवा

विरुद्ध

— आवेदकगण

- 1- राजमोहन सेन उर्फ लल्लू तनय स्व. रामनिहोर
नि० मोहल्ला पाण्डेन टोला, तह. हुजूर, जिला रीवा
- 2- श्रीमती शान्ती देवी विधवा स्व. रामदास पुत्री स्व. रामनिहोर
नि० सन्तोषी माता मंदिर, टेकहा, तह० हुजूर
- 3- श्रीमती मायादेवी उर्फ छोटेबाई पत्नी राममेश
पुत्री स्व. रामनिहोर, नि० सर्रा पीपर, रांझी, जबलपुर
- 4- श्रीमती दला सेन उर्फ बिट्टी पत्नी रमेश पुत्री स्व. रामनिहोर
नि० गैस गोदाम के सामने सिध्दार्थनगर, सतना
- 5- कु. सुमन उर्फ गुधन पुत्री स्व. चन्द्रमोहन सेन
- 6- राहुल सेन उर्फ लाला तनय स्व. चन्द्रमोहन सेन
- 7- रोहितसेन उर्फ बुल्ली तनय स्व. चन्द्रमोहन सेन
क 5 से 7 नि० मोहल्ला पाण्डेनटोला, तह. हुजूर जिला रीवा

— अनावेदकगण



21.4.2014

श्री अमर ज्योति गुप्ता, अभिभाषक - आवेदकगण
श्री जयप्रकाश मिश्रा, अभिभाषक- अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21.12.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 314/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

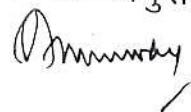
2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि शंकरदीन द्वारा प्लॉट नं0 2885 रकबा 0.08 डि. पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 30-8-02 द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध रामनिहोर द्वारा अपील नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नजूल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03-08-10 में यह निष्कर्ष निकाला कि तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 29-6-65 द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट 2885 के कुल रकबा 0-08 में से 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये, इस कारण इसी प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः नामान्तरण के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। अतः नजूल अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर तहसील का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 23 12 11 द्वारा खारिज की गयी है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि एकबार नामान्तरण होने के बाद उसी भूमि का नामान्तरण किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तथा अपीलार्थी का दावा मान.



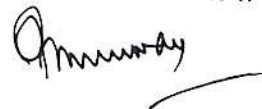
सिविल न्यायालय द्वारा भी निरस्त हो चुका है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। निगरानी आवेदन में आवेदकगण द्वारा मुख्य रूप से यह गुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पूर्वज कंधी नाई के नाम दर्ज हैं जो काफी समय पूर्व मृत हो गये हैं। मृत रामनिहोर द्वारा कराया गया नामान्तरण फर्जी एवं कूटरचित है जिसकी कोई जानकारी ना तो शंकरदीन को थी और ना ही आवेदकगण को है। नजूल खसरो में भी नामान्तरण की कोई इत्तलायाबी दर्ज नहीं है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित नामान्तरण तहसीलदार, हुजूर द्वारा पारित है जो अधिकारितारहित है क्योंकि तहसीलदार को नजूल भूमि पर नामान्तरण की अधिकारिता नहीं है। नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि थी। समयावधि विधान की धारा 5 में दर्शित आधार पूर्णतया निराधार एवं बनावटी है और प्रत्येक दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तहसील का आदेश पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में तहसीलदार, नजूल द्वारा आदेश दिनांक 29-6-65 पारित किया जा चुका है, इस कारण पुनः नामान्तरण करने की अधिकारिता तहसील को नहीं थी। तहसील न्यायालय में रामनिहोर को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर नजूल अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में थी। उनका यह भी तर्क है कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट के संबंध में शंकरदीन का दावा खारिज किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया

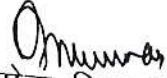


5/ नजूल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03-08-2010 में यह निष्कर्ष निकाला है कि तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 29-6-65 द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट 2885 के कुल रकबा 0-08 में से 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये, इस कारण इसी प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः नामान्तरण के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। नजूल अधिकारी द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष की पुष्टि नजूल अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 135 से 141 पर उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रति से होती है। तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदनपत्र कंधी की मृत्यु होने पर शंकरदीन एवं रामनिहोरे द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 17/ए-6/64-65 में आदेश दिनांक 29-6-65 द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट नं0 2886 के 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये हैं। नजूल अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 145 पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक, नजूल के प्रतिवेदन दिनांक 23-6-82 में यह अंकित है कि 'मुताबिक आवेदनपत्र बन्दो. खसरा नं0 2885 रकबा 0.08 में कंधी हजाम का नाम दर्ज है जो मुता. आदेश तहसील हुजूर दिनांक 29-6-85 प्र.क. 17/ए-6/64-65 बन्दो. खसरा नं0 2885 में से 0.02 डि. शंकरदीन नाई तथा 0.06 डि. में रामनिहोर नाई का नाम दर्ज है/किया गया है।' कंधी की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नाधीन प्लॉट पर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के उपरान्त पुनः तहसील न्यायालय को नामान्तरण की अधिकारिता नहीं है। यदि आवेदकगण या उनके पिता शंकरदीन उक्त नामान्तरण आदेश से असन्तुष्ट थे तो उन्हें राक्षम न्यायालय में उसे चुनौती दी जाना चाहिये थी। शंकरदीन द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में रामनिहोर को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30-8-02 पारित करने के पूर्व रामनिहोर को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किया और ना ही रामनिहोर को आदेश की सूचना देने का प्रमाण है। संहिता की धारा



47 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहाँ आदेश पारित करने के दिनांक की सूचना ना ही समयावधि की गणना आदेश की संसूचना/जानकारी के दिनांक से करने का प्रावधान है। ऐसी दशा में नजूल अधिकारी द्वारा अपील समयावधि में मान्य करने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट टेक कोर्ट) रीवा ने भी व्यवहार अपील 91ए/2004 रामनिहोर एवं राजमोहन विरुद्ध मृत शंकरदीन निर्णय दिनांक 29-9-04 द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट नं. 2885 के संबंध में अपील स्वीकार कर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा दी गयी स्थाई निषेधाज्ञा एवं डिकी को खारिज किया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 23-12-11 तथा नजूल अधिकारी का आदेश दिनांक 03-08-10 यथावत रखे जाते हैं।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0